Indian promoters did not arise. Further, as per the then guidelines of Reserve Bank of India the banks were not to insist upon the personal gurantees of Directors for loan given to industrial concerns.

(d) The Indian overseas Banks which was the lead bank in the consortium has reported that the consortium of banks are having first charge on the fixed and current assets of P.T. Five Star Industries Limited.

(e) In accordance with the statutes governing the Public Sector Banks and amongst the bankers, information the practices and usages customary amongst the bankers, information relating to or to the affairs of the constituents of the banks cannot be divulged.

अपने मकानों में रह रहे व्यक्तियों के मकान किराया भत्ते पर आयकर लगाया जाना

2163. डा० गोबिन्द दास रिछारिया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों/आयकर अपील अधिकरणों के फैसलों और केन्द्रीय सरकार के वर्तमान आदेशों के परस्पर विरोधी मतों के कारण अपने मकानों में रहने वाले निर्धारित वेतन भोगी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते पर आयकर लगाने के बारे में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ; और

(ग) क्या सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों को सम्मान देते हुए आयकर दाताओं के मध्य इस भेदभाव को समाप्त करने का विचार रखती है ताकि सभी संबंधितों के ध्यान में सही स्थिति लाई जा सके और भेदभाव समाप्त किया जा सके और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गदवी) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम की धारा 10 (13क) में ऐसे विशेष भत्ते को छूट दी गई है जो किसी निर्धारिती द्वारा उसके अधिभोग में निवास स्थान की बाबत किराये के संदाय पर वास्तव में उपगत व्यय की पूर्ति के लिये उसे निर्धारिती के नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उस परिणाम तक दिया गया हो जो विहित किया जाये। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2क में मकान किराये भत्ते की वह राशि विनिर्दिष्ट की गई है जिसके लिये इस धारा के तहत छूट है।

आयकर आयुक्त बनाम न्यायमूर्ति एस० सी० मित्तल (1980) 121 आई टी आर 503 के मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्णय दिया था कि यह छूट अपने निजी मकान का अधिभोग करने वाले किसी कर-निर्धारिती और जिसने अपने नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त किया हो, के लिये भी स्वीकार्य होगी। इस निर्णय का अनुसरण उच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्व न्यायाधीश बी० आर० तुली, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (1980) 125 आई०टी०आर० 460 और एम० एस० गुजराल, मुख्य न्यायमूर्ति सिक्किम उच्च न्यायालय (1980) 125 आई. टी. आर 655 के मामलो में भी किया गया था। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आल इंडिया लक्ष्मी कमर्शियल बैंक आफीसर्स यूनियन (1984) 150 आई०टी०आर० के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न मत प्रकट किया था और इसने यह अभिनिर्णय दिया था कि जो कर-निर्धारिती अपने निजी मकानों में वास्तव में रहते हैं और मकानकिराया भत्ता प्राप्त करते हैं, वे इस छूट को पाने के हकदार नहीं है।

चूंकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय मूल आशय के अनुरुप नहीं थे, अतः धारा 10 (13क) में कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम,

1984 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव 1 अप्रैल 1976 से एक व्याख्यात्मक टिप्पणी जोड़ दी गई है जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है और जो सरकार की नीति के अनुसार है।

Notices issued for under-valuation of properties

2164. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Income Tax Department have issued notices for acquiring/have acquired properties all over the country on account of under-valuation of these properties;

(b) if so, what are the details of such properties with dates of serving notices property acquired during the last one year;

(c) whether some of the landlords have represented to the Government on this account and if so, the reaction of the Government thereto;

(d) whether it is a fact that in some cases the value of the properties have increased due to the change of status of these properties; and

(e) if so, whether Government propose to take the value of these properties as on the date of signing an agreement between the buyer and purchaser and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) and (b) A new Chapter XXC conferring on the Central Government a pre-emptive right to purchase an immovable property has been inserted in the Income-tax Act and the provisions of this Chapter have come into force w.e.f. 1st October 1986. Vide Notification No. S. O. 480(E) dated 7th August 1986, these provisions are effective in the metropolitan cities of Bombay, Calcutta, Delhi and Madras only. The provisions in this new Chapter do not rovide for compulsory acquisition f immovable property but merely enable the Central Government to purchase a property which has already been offered for sale. Till 31-7-1987 orders for pre-emptive purchase under section 269UD(1) of the I.T. Act have been passed in respect of 106 such properties. A statement giving the details is given in the Annexure (*See* Appendix CXLIII, Annexure No. 95)

(c) Yes, Sir. The Government have recevied some petitions from the individual parties interested in the transaction. So far the orders passed by the Appropriate Authority under section 269UD(1) have been found to be just and fair.

(d) Under the scheme of this chapter, the Statement of the proposed transfer of the property is filed by each of the parties to such transfer, declaring the apparent consideration. Thereafter, the Appropriate Authority may make an order under section 269UD after recording the reasons in writing for the purchase of the immovable property at an amount equal to the amount of apparent consideration. After such order is passed by the Appropriate Authority, the property vests in the Central Government free from all encumbrances. It is a fact that in all cases where orders under section 269UD(1) are passed, the value of the property increased due to change of ownership from individual owner to Central Government.

(e) Question does not arise. The order section 269UD(1) is based taking into account the apparent consideration declared in the statement filed by each of the parties to such transfer.

Opening of an additional channel

2165. SHRI CHANDRIKA PRASAD TRIPATHI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether some state Governments have asked the Central Government for opening of an additional